

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

खण्ड A

बाल श्रम : एक आवश्यक बुराई या केवल एक बुराई ?

" बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। "

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. शफीजे अब्दुल कलाम का यह कथन किसी देश के लिए बच्चों के भएव को इंगित करता है। निश्चित रूप से बच्चों के सकारात्मक विकास से देश का सकारात्मक विकास सुनिश्चित हो पाता है क्योंकि बड़े होकर ये बच्चे ही देश के भाग्य को सही या गलत दिशा प्रदान करते हैं। परन्तु बाल श्रम बच्चों के सकारात्मक विकास के समक्ष एक सर्वाधिक विकट चुनौति ~~बिच~~ प्रानी जाती है।

बाल श्रम न सिर्फ बच्चे के सर्वांगीण विकास को बाधित करता है अपितु यह देश के भी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विकास

के समक्ष एक काले धब्बे का कार्य करता है। भारत और विश्व के अनेक देशों में यह बुराई बच्चों के भविष्य को दीमक बनकर खाई जा रही है।

भारत में यह बुराई प्राचीन काल से ही प्रचलित है। हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात अनेक प्रयासों के फलस्वरूप इस बुराई की भयावहता में कभी देखने को मिल रही है परन्तु यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी विश्व के सर्वाधिक बाल श्रमिक भारत में निवास करते हैं। यह तथ्य भारत के भविष्य के समक्ष एक संकट के रूप में विद्यमान है।

अब यदि चर्चा की जाए कि इस समस्या के पीछे सैन-सैन से कारक जिम्मेदार हैं? तो पता लगता है कि इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक इत्यादि सभी कारकों

का सम्मिलित योगदान है। भारत में वैतहाशा जनसंख्या श्रुष्टि तथा परिवार नियोजन के अभाव के कारण बच्चों की आवश्यकतानुसार मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पाती तथा परिवार के पैट पालन के लिए उन्हें बाल श्रम के दलदल में धकेल दिया जाता है।

इसी के साथ ही गरीबी तथा शिक्षा के अभाव के कारण माता-पिता बच्चे की कम उम्र में ही आजीविका के लिए तैयार करने के लिए उसे बाल श्रमदूरी पर भेज देते हैं। इसके पीछे सरकारी शिक्षा व्यवस्था की असफलता की उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। बाल श्रमकारी में संलग्न लोग बच्चों की अपहृत करके उनसे खानों, कारखानों तथा शॉपों पर बलात् श्रम करवाते हैं। वहीं लड़कियों को अवैध यौन व्यवसाय में धकेल दिया जाता है।

कई बार माता-पिता अपने तद्वण की चुकाने के लिए बच्चों की साहूकार के पास

भजदूरी करने के लिए भेज देते हैं, जहां उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया जाता है। कारखानों के भालिक काल श्रमिकों को वरीयता देते हैं क्योंकि वे कम भजदूरी में कार्य करते हैं तथा उनको अपने अधिकारों का स्ान न होने के कारण, वे अन्याय का विरोध नहीं करते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बाल श्रम के पीछे अनेक कारक जिम्मेदार हैं। परन्तु बाल श्रम को एक आवश्यक बुराई नहीं माना जा सकता क्योंकि यह बच्चों के हितों को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं पहुंचाती तथा उनके वर्तमान तथा भविष्य को पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। यह सरकारी योजनाओं की विफलता के कारण उत्पन्न होती है इसलिए उपयुक्त प्रयासों के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है। इसलिए बाल श्रम को केवल एक बुराई माना जाना चाहिए, जो देश के

विकास एवं भविष्य के समक्ष एक विकराल चुनौती है तथा बच्चों के गलत विनाशकारी हैं। यह बच्चों के माता-पिता की भ्रष्टाचारी के कारण उत्पन्न होती है न कि जान-बूझकर।

बाल श्रम बच्चों के बहुआयामी विकास को बाधित कर उन पर अनेक नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके कारण बच्चों के सुकुमार बचपन का विनाश तो होता ही है, साथ-साथ उनके शारीरिक, शैक्षिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास को भी अवरुद्ध करने का कार्य बाल श्रम करता है।

बचपन की अवस्था बच्चों में विचारों के विकास की अवस्था माना जाता है। बाल श्रम द्वारा इन विचारों को अवरुद्ध कर बच्चों की सृजनशीलता का विनाश करता है। खतरनाक व्यवसायों में कार्य करने से वे बीमारी या कभी-कभी तो मृत्यु का भी शिकार हो जाते हैं। बच्चों के शैक्षिक विकास के अवरुद्ध होने से वे

कुशल मानव पूंजी में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं तथा इसके कारण दीर्घकाल में देश के आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इसी के साथ बाल श्रम के कारण बच्चों की उनकी क्षमता से ज्यादा कार्य करने तथा उचित पोषण न मिलने के कारण वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं जिसके आगे चलकर दृग्गामी प्रभाव होते हैं। बाल श्रम से देश के जनसांख्यिकीय लाभान्ध पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो देश की विकास क्षमता को अवरुद्ध करता है।

अतः स्पष्ट है कि बाल श्रम एक ऐसी बुराई है जो बच्चों के भविष्य के साथ-साथ देश के भविष्य पर भी खतरा प्रस्तुत करती है। इसीलिए समय-समय पर बाल श्रम को रोकने के लिए वैश्विक स्तर, संवैधानिक स्तर, वैधानिक स्तर, प्रशासनिक स्तर तथा सिविल समाज स्तर पर अनेक प्रयास किये गए हैं।

वैश्विक स्तर पर युनिसेफ जैसी संस्था बच्चों के विकास हेतु तथा बाल श्रम को रोकने हेतु समय-समय पर अनेक नीतियों का निर्माण एवं कार्यक्रमों का संचालन करती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम पर अनेक अभिसमयों का निर्माण किया है। हाल ही में भारत ने 'ILO' के ही अभिसमयों पर हस्ताक्षर किया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी को निषेध किया गया है तथा इसी के साथ अनुच्छेद 39, 45, अनुच्छेद 51A के तहत भी बच्चों के विकास हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं।

भारत में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन तथा बाल श्रम (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 पारित किया गया। हाल ही बाल श्रम प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया जिसे 14 वर्ष तक के सभी बच्चों ~~के~~ से किसी भी प्रकार का श्रम करवाना और कानूनी एवं 505वीं अपराध घोषित किया गया है।

इसी के साथ सरकार ने बच्चों के कल्याण

के लिए मिड-डे-मिल स्कीम, एक समेकित बाल विकास सेवा (ICDS), ~~प्रारंभिक~~ ^{सर्व} शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), बाल श्रमिकों हेतु पुनर्वास योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान इत्यादि कार्यक्रमों एवं योजनाओं का शुभारंभ किया है।

अनेक गैर-सरकारी संस्थान जैसे प्रथम फाउंडेशन, कैलाश सत्याधी फाउंडेशन, क्राई, बिल गेट्स एण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इत्यादि भी बाल कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं।

उपर्युक्त बहुआयामी प्रयासों के कारण समय के साथ इस बुराई को कम करने में सहायता अवश्य मिली है परन्तु अभी भी यह बुराई व्यापक स्तर पर विद्यमान है। इसके पीछे अनेक कारण हैं, जैसे सरकारी विद्यालयों एवं योजनाओं का अप्रभावी क्रियान्वयन; विभिन्न मंत्रालयों तथा योजनाओं के मध्य समन्वय का अभाव; बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम में

पारिवारिक श्रम की निश्चित परिभाषा का अभाव होना;
बाल कल्याण कार्यक्रमों की पहुँच में प्रौद्योगिकी
का निम्न प्रयोग; जन-जागरूकता का अभाव इत्यादि

इसलिए सरकार को इस पुराई के
निवारण के लिए अपने कार्यक्रमों एवं योजनाओं
की व्यापक स्तर पर समीक्षा करके उनके प्रभावी
क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए। सरकारी
योजनाओं में उचित समन्वय को सुनिश्चित
कर परिणामों की प्रभावशीलता में वृद्धि करने
का प्रयास करना चाहिए। अधिकाधिक पहुँच
सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक
स्तर पर प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ
सरकार को निजी संस्थाओं एवं गैर-सरकारी
संगठनों को अपने प्रयासों के पूरक के
तौर पर शामिल करना चाहिए।

साथ ही सोशल मीडिया, प्रिन्ट एवं
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बाल श्रम के
बु प्रभावों तथा कल्याणकारी योजनाओं के बारे

में व्यापक जनजागरण का प्रयास करना चाहिए।

अब यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि हाल श्रम अनेक पारिस्थितिक कारणों से उत्पन्न हुई बुराई है जिसमें परिवार का आकार, आय का स्तर, अवस्थिति तथा सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता की कमी इत्यादि का सम्मिलित योगदान होता है। यह बच्चों एवं देश के विकास दोनों के लिए सभी रूपों में अहितकर है। यह बच्चों के सुकुमार व भोले बचपन का विनाश करके उनके जीवन को अंधकार की ओर धकेलता है। अतः इसे एक आवश्यक बुराई न मानकर केवल एक बुराई माना जाना अधिक सही प्रतीत होता है। साथ ही बच्चों एवं देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तत्काल प्रभाव से बहुसंस्थागत एवं बहुआयामी तथा प्रभावी कदमों की आवश्यकता है।

इससे न केवल बच्चों के जीवन में ज्योति का समावेश होगा बल्कि सतत विकास लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सहायता मिलेगी। इसलिए सरकार एवं समाज को इस दुर्घाई को गंभीरता से लेकर इसके बहुआयामी नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इसके समूल विनाश का प्रयास करना चाहिए।

अन्य में बॉलीवुड फिल्म का एक जाना भरे मन में आता है जो बच्चों की विशेषता का सहीकता से वर्णन करता प्रतीत होता है-

“ बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँखों के तारे।
ये वो नन्हें फूल हैं जो भगवान को लगते धारें।”

इसलिए बच्चों की कोमलता एवं असीम संभावनाओं की सुरक्षा के लिए बाल भ्रम जैसी दुर्घाई का तत्काल नाश सभी के हित में होगा।

आसियान - भारत : साक्षा मूल्यों और समान नियमों
के समक्ष उभरती चुनौतियां

हाल ही में संपन्न हुए 50 वें आसियान सम्मेलन तथा 25 वें भारत- आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने अपना व्यक्तव्य दिया कि भारत और आसियान न सिर्फ साक्षा मूल्यों और समान नियमों को धारण करते हैं अपितु वे साझी चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं जिन पर परस्पर सहयोग के माध्यम से विजय प्राप्त की जा सकती है।

प्रधानमंत्री का यह व्यक्तव्य भारत-आसियान संबंधों की न सिर्फ ऐतिहासिकता एवं वर्तमान का उल्लेख करता है अपितु भविष्य की संभावनाओं एवं चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है तथा दोनों पक्षों की साझा प्रयास एवं सहयोग बढ़ाने की प्रेरित करने का प्रयास करता है।

आसियान की स्थापना 1960 के

दशक में दक्षिण-पूर्वी एशिया के 5 देशों के की। बाद में इसमें 5 देशों के और जुड़ जाने के कारण वर्तमान में इसमें 10 देश सदस्य हैं जो क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक विकास एवं सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल देते हैं। ये तो भारत और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संबन्ध प्राचीन चोल काल से है परन्तु स्वतंत्रता से लेकर 1992 तक भारत इस ओर अपना ध्यान न दे सका। 1992 में भारत ने अपनी लुक ईस्ट नीति के माध्यम से आसियान देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबन्ध स्थापित किए।

वर्तमान में भारत आसियान के साथ एक रणनीतिक साझेदार तथा मुक्त व्यापार भागीदार बन चुका है। भारत-आसियान के मध्य वर्तमान में अनेक क्षेत्रों में संबन्ध मौजूद हैं जिनके भविष्य में ओर अधिक विस्तृत होने की संभावना है।

भारत एवं आसियान देश अनेक साझा मूल्यों को धारण करते हैं। प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक जुड़ाव के कारण एक-दूसरे की संस्कृति की काफी समझ है। भारत से जन्मा बौद्ध धर्म बाद

में इन देशों में फैल गया जो वर्तमान में कई आसियान देशों का राजकीय धर्म है तथा सहिष्णुता एवं शान्ति के मूल्यों पर बल देता है। इसी के साथ बाली द्वीप, थाइलैण्ड में अनेक हिन्दू मन्दिरों के होने तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों के होने के कारण यहां के लोगों का एक-दूसरे के देशों में आना जाना लगा रहता है।

भारत और आसियान दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था का सम्मान करने के पक्षधर हैं तथा दक्षिणी हिन्द महासागर में चीन के अवैध कब्जे का विरोध करते हैं। ये दोनों पक्ष भुक्त परिवहन तथा भुक्त व्यापार का सम्मान करते हुए संरक्षणवाद का विरोध करते हैं। आतंकवाद एवं कट्टरवाद का तीव्र विरोध करने के साथ-साथ जलवायु ~~प्रदूषण~~ परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए साझा प्रयासों पर बल देते हैं।

इसी के साथ दोनों पक्ष हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान

करने के सिद्धांत के पक्षधर^{होने} के साथ-साथ इस क्षेत्र में शान्ति एवं स्थिरता के भी समर्थक हैं। दोनों पक्ष चीन के बढ़ते प्रभुत्व एवं आक्रामक को रोककर शक्ति संतुलन स्थापित करने के पक्ष में हैं तथा आपस में बहुआयामी सहयोग पर बल देते हैं।

~~संस्था~~ संस्था मूल्यों के साथ साथ भास और आसियान देश संस्था लक्ष्यों को भी धारण करते हैं। दोनों पक्षों में अनेक देश जारी रखे हुए भुखमरी का सामना कर रहे हैं जिनका निवारण आपसी सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है। दोनों पक्षों के मध्य व्यापार अभी संभावित क्षमता से अत्यंत कम है जिसे बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष तत्पर हैं। वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के समझौते पर ~~ए~~ बातचीत जारी है। यह आसियान देशों व ~~अन्य~~ भारत समेत अन्य पांच देशों के मध्य भुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करेगा।

दोनों पक्ष चीन के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते प्रभुत्व व अपनी सामरिक सुरक्षा को लेकर चिन्तित हैं। इसलिए दोनों पक्ष मिलकर इसका सामना करना चाहते हैं। दोनों पक्षों के मध्य ब्लू इकोनमी के क्षेत्र में व्यापक साझेदारी की संभावनाएं मौजूद हैं तथा समुद्री आतंकवाद एवं समुद्री प्रदूषण से निपटारे के लिए व्यापक सहयोग अपेक्षित है।

दोनों क्षेत्र के अनेक देश जलवायु परिवर्तन की नकारात्मकताओं से पीड़ित हैं। इसलिए वैश्विक मंचों पर एक साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाने में सहयोग की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। अवसंरचनात्मक विकास व कनेक्टिविटी के क्षेत्र में व्यापक सहयोग अपेक्षित है। भारत ~~के~~ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उभरती शक्ति है तथा वह आसियान क्षेत्र को बाजार के तौर पर देख सकता है।

इसी के साथ अनेक दक्षिण-पूर्वी एशियाई

देश जैसे सिंगापुर इत्यादि भारत में FDI के बड़े स्रोत हैं तथा भारत के लिए भी ब्यांमार के तेल क्षेत्रों तथा विद्युत् नाम जैसे देशों में व्यापक निवेश की संभावनाएँ मौजूद हैं। दोनों ~~पक्ष~~ ^{पक्ष} साझी संस्कृति के कारण आपसी पर्यटन के माध्यम से अपना सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास कर सकते हैं।

इसी के साथ-साथ भारत व आसियान दोनों क्षेत्र चक्रवात एवं सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं। अतः दोनों पक्षों के बीच इस क्षेत्र में व्यापक सहयोग एवं संचारना के अवसर मौजूद हैं।

उपर्युक्त संभावनाओं एवं अवसरों के दोहन के लिए दोनों पक्षों द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। भारत आसियान का रणनीतिक साझेदार होने के नाते प्रतिवर्ष होने वाले आसियान सम्मेलन में भाग लेता है। इसी के साथ-साथ प्रतिवर्ष भारत-आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित करने के साथ-साथ अनेक द्विपक्षीय वार्तियाँ भी आयोजित की जाती हैं जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों के साथ-साथ

वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक विचार विमर्श किया जाता है। हाल ही में सैन्य-भारत-आसियान व शिखर वार्ता के दौरान व्यापार क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, आपदा प्रबंधन व समुद्री सहयोग इत्यादि क्षेत्रों में अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत 2014 के बाद अपनी पुरानी लुक ईस्ट नीति के स्थान पर एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी सक्रिय उपस्थिति को सुनिश्चित करने का निरन्तर प्रयास कर रहा है तथा आपस में भौतिक एवं सांस्कृतिक कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। भारत-म्यांमार-थाइलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, जिसके लाओस एवं वियतनाम तक विस्तार की संभावना है; कलादान मल्टीमॉडल पारगमन प्रोजेक्ट; विमसरेक के माध्यम से सहयोग बढ़ाना इत्यादि प्रमुख प्रोजेक्ट हैं।

इसी के साथ भारत वियतनाम में तेल क्षेत्रों में ONSC विदेश लिमिटेड के माध्यम से निवेश कर रहा है। साथ ही आसियन देशों

को भी अपने मेक इन इण्डिया कार्यक्रम, स्मार्टअप इण्डिया, स्मार्ट सीट सिटी मिशन, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम इत्यादि में निवेश करने की प्रोत्साहित कर रहा है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु साझा अभ्यास पर बल दे रहा है तथा सामरिक सहयोग को मजबूत करने के लिए थाइलैण्ड, सिंगापुर, फिलीपिन्स, इंडोनेशिया इत्यादि देशों के साथ समय-समय पर सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है।

अब कहा जा सकता है कि दोनों क्षेत्र व्यापक सहयोग को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं। परन्तु इन दोनों पक्षों के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं जिनका समाधान क्रिये बिना ये अपने-साझे लक्ष्यों की प्राप्ति करने में कठिनाई का सामना करेंगे।

दिए गए प्रश्न क्षेत्र में चीन अपनी वन बेल्ट - वन रोड (OBOR) जैसी महत्वाकांक्षी

परियोजना तथा स्ट्रिंग ऑफ पर्थ के एवं दक्षिण चीन सागर में अपने अवैद्य कब्जे के माध्यम से अपनी उपास्यता एवं प्रभुत्व को आक्रामक रूप से बढ़ा रहा है, जो दोनों पक्षों के समक्ष सुरक्षा एवं संप्रभुता संबंधी चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है।

चीन दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में अपने निवेश को लगातार बढ़ाकर तथा व्यापार द्वारे को अपने पक्ष में करके इन देशों को अपना आर्थिक गुलाम बनाने का प्रयास कर रहा है साथ ही भारत भी चीन के साथ लगभग 71 बिलियन डॉलर के व्यापार द्वारे का सामना कर रहा है।

दोनों क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन के घटने, भूतल में कमी आने, चक्रवातों की संख्या में वृद्धि होने, समुद्री तल में वृद्धि जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तथा साथ ही समुद्री क्षेत्र में तेल निष्कर्षण, खनिज निष्कर्षण, तेल रिसाव, ठोस & अपशिष्ट एवं

जलवायु प्रदूषण इत्यादि समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इंडोनेशिया के द्वीपीय क्षेत्र एवं आंडमान सागर में समुद्री उर्वरता के कारण समुद्री व्यापार की सुरक्षा को लेकर दोनों पक्ष चिन्तित हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े संरक्षणवाद के कारण भुक्त ~~व्यापार~~ व्यापार प्रणाली को ठेस पहुंची है तथा इसके कारण दोनों पक्षों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

दोनों क्षेत्र हिन्द-महासागर व प्रशांत महासागर के सुनामी एवं चक्रवात प्रभावित स्थानों को समर्थित करते हैं। 2004 में आयी सुनामी के कारण दोनों क्षेत्रों में लाखों लोगों की मृत्यु के साथ अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। भूत 3 घण्टा ~~अ~~ आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

इसके अलावा धार्मिक कट्टरवाद व आतंकवाद के प्रसार, शरणार्थियों की समस्या इत्यादि चुनौतियां भी दोनों पक्षों के समक्ष उपस्थित हैं अतः आवश्यक है कि इन चुनौतियों के समाधान

के लिए दोनों पक्षों के मध्य सहयोग को और अधिक विस्तृत एवं गहरा करना समय एवं परिस्थितियों की भाँग है।

चीन के प्रभुत्व एवं आक्रामकता को रोकने के लिए बहुपक्षीय अंशों पर सहयोग बढ़ाने तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। नियमित सैन्य अभ्यासों के साथ-साथ रक्षा प्रौद्योगिकी विनिमय पर बल दिया जाना चाहिए। जैसे भारत विपतनाम को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की योजना बना रहा है।

जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी व विनीय सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय अंशों पर विकसित देशों पर विनीय समर्थन के लिए ~~सहयोग~~ ~~का~~ ~~डबाव~~ बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। भारत इसके साथ ही परमाणु आश्मि-कर्ता समूह (NSG) तथा सुरक्षा परिषद में प्रवेश के लिए इन देशों का समर्थन प्राप्त कर सकता है।

दोनों पक्षों के मध्य निवेश तथा

व्यापार वाणिज्य को बढ़ाकर तथा पर्यटन के क्षेत्र में व्याप्त संभावनाओं का फ़ौन करते सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।

समुद्री पारिस्थिती तथा समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए साझा प्रयास करने के साथ-साथ एनडी (कोनमी) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना अपेक्षित है। इसी के साथ अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों से निपटने, आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है।

आतंकवाद एवं कट्टरवाद से निपटने के लिए आपस में सूचना एवं इंटेलिजेंस ~~सूचना~~ साझाकरण का प्रयास किया जाना चाहिए। शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ-साथ सुरक्षा चिन्ताओं को भी ध्यान में रखने का प्रयास किया जाना चाहिए।

अतः स्पष्ट है कि दोनों पक्ष अपने-अपने साझा मूल्यों एवं साझा नियमों की संभावनाओं से लाभ प्राप्त करने तथा साझी चुनौतियों से

निपटने के लिए वृद्धायामी प्रयास कर सकते हैं। आस
के आख्यान के साथ संबन्धों से आर्थिक विकास को
बढ़ाने के साथ-साथ चीन के प्रभुत्व को कम करने,
उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास एवं सुरक्षा को सुनिश्चित
करने, समुद्री ~~बा~~ पारदर्शी व प्रदूषण से निपटने,
ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में व्यापक
लाभ मिलने की संभावनाएं मौजूद हैं, जिनका
उपयुक्त नीति निर्माण तथा उसके मुदनीतिक स्तर
पर सही डिमान्वयन के माध्यम से दोहन किया
जा सकता है। इसके दोनों पक्षों के मध्य
विश्वास में वृद्धि के साथ-साथ उज्ज्वल भविष्य
की स्थापना में मदद मिलेगी। परन्तु इस
संबन्ध में सही प्रयास अभी प्रारंभिक स्तर
पर है जिनको निरन्तर बढ़ाने की आवश्यकता
है।

अन्त में ये पंक्तियां इन दोनों के संबन्धों
के लिए उपयुक्त प्रतीत होती हैं-

"~~अभी~~ ~~ये~~ भीलों साथ हम आ गये, भीलों
हमें चलना बाकी है।"

